

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

बीकानेर

Rashtradoot

फोन:- 2200660 फैंक्स : 0151-2527371

वर्ष: 47

संख्या: 35

प्रभात

बीकानेर, बुधवार 27 अगस्त, 2025

डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22

पृष्ठ 6

मूल्य 2.50 रु.

अंबानी के “वनतारा” की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित की

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस चेलमेश्वर के नेतृत्व वाली एसआईटी को 12 सितम्बर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 26 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात स्थित अनंत अंबानी द्वारा स्थापित ‘वनतारा’ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) का गठन किया है।
अदालत ने कहा कि सामान्यतः ऐसे आरोपों पर आधारित याचिका, जिनके समर्थन में कोई ठोस सबूत न हो, कानून की दृष्टि में विचारणीय नहीं होती और प्राथमिक स्तर पर ही खारिज की जानी चाहिए।

इसके बावजूद, कोर्ट ने मामले की तथ्यात्मक जांच पड़ताल के लिए जांच आवश्यक मानी है और एसआईटी को 12 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।
एसआईटी का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस जस्ती चेलमेश्वर करेंगे और आयोग के अन्य

■ सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश एडवोकेट जया सुकीन व देव शर्मा की याचिका पर दिए जिनमें अखबारों में छपी खबरों के आधार पर पशु अधिकारों के हनन व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।

■ कोर्ट ने एसआईटी गठित करते समय हालांकि यह भी कहा, कि जिन आरोपों की पुष्टि के लिए ठोस सबूत न हों वे याचिकाएं खारिज कर दी जानी चाहिए पर इस मामले से तथ्यात्मक जांच जरूरी है।

■ वनतारा असल में वन्यजीवों का पुनर्वास केन्द्र है जहां देश विदेश से जंगली जानवर लाए जाते हैं। इस केन्द्र की स्थापना अनन्त अंबानी ने की है।

सदस्य होंगे, बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, राघवेंद्र चौहान, मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त हेमंत नगराले तथा अतिरिक्त आयुक्त, कस्टम्स अनीश गुप्ता।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस पंकज मिथल और पीबी वराले की बैंच ने यह

याचिकाओं में लगाए गए आरोप अखबारों में छपी रिपोर्टों पर आधारित हैं और उनके समर्थन में कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किए गए। फिर भी, अदालत ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करने की बजाय, एक तथ्यान्वेषण जांच का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने से जिन मुद्दों पर रिपोर्ट मांगी है, उनमें शामिल हैं: वनतारा द्वारा भारत और विदेशों से जानवरों, विशेष रूप से हाथियों का अधिग्रहण किन परिस्थितियों में और किस प्रक्रिया से किया गया।

क्या ये गतिविधियाँ वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, तथा चिड़ियाघर नियमों के अनुरूप हैं? क्या जानवरों या उनके उत्पादों के व्यापार संबंधी नियमों का पालन किया गया है? क्या वहां पशुपालन, पशु चिकित्सा देखभाल और पशु कल्याण से संबंधित मानकों का पालन हो रहा है?

वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन में 6 की मौत

जम्मू, 26 अगस्त। जम्मू के पास कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी मार्ग में अर्धकुवारी के पास मंगलवार को भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गयी और 14 अन्य घायल हो गये हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यह जानकारी दी।

श्राइन बोर्ड ने कहा कि अर्धकुवारी के पास हुए इस भूस्खलन में घायल हुए लोगों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। दूसरी ओर जम्मू के सभी स्कूल बुधवार को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। श्राइन बोर्ड और सुरक्षा बलों ने राहत और

■ श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी तौर पर रोक दी गई।

बचाव कार्य शुरू कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर माता वैष्णो देवी की यात्रा को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। अर्धकुवारी से भवन तक का मार्ग बंद कर दिया गया है। निचले ट्रंक से भी श्रद्धालुओं की आवाजहोी सीमित कर दी गई है। जम्मू प्रशासन ने खराब मौसम और क्षेत्र भर में अलग अलग स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने के मद्देनजर सभी सरकारी और निजी स्कूल कल बंद रखने का निर्देश दिया है।

कौन पैदा करवा रहा है “ट्राइबल लीडर” बिरसा मुंडा और अम्बेडकर के बीच टकराव की स्थिति?

कोटा में भारतीय रेल्वे एस.सी./एस.टी. एसोसिएशन को आवंटित आवास में अम्बेडकर की मूर्ति के समक्ष अनाधिकृत तरीके से क्यों लगाई गई बिरसा मुंडा की मूर्ति?

■ जर्मन अखबार ने दावा किया कि ट्रंप की धमकियाँ व दबाव भारत पर काम नहीं कर रहे।

को आम रणनीति, शिकायतें, धमकियाँ और दबाव, भारत के मामले में काम नहीं कर रही हैं, जबकि कई अन्य देशों के साथ ऐसा हो रहा है। हालाँकि, इस दावे के बारे में पुष्टि नहीं हो पाई है।
मीडिया वेबसाइट वियॉन ने एफ.ए.जेड. का हवाला दिया है, जिसमें यह दावा किया है कि अगर जर्मन भाषा की रिपोर्ट का मशीनी अनुवाद सही है, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-यादवेंद्र शर्मा-
जयपुर, 26 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने भारतीय रेल्वे की अनुसूचित जनजाति के लिए गठित एसोसिएशन को कोटा आर्बिट्रट मकान के परिसर में अनाधिकृत और अवैध तरीके से बिरसा मुंडा की मूर्ति स्थापित करने के मामले में सुनवाई की और एसोसिएशन की कोटा ज़ोन की ईकाई को राहत देते हुए आदेश दिए हैं कि 7 दिन के भीतर इस एसोसिएशन के द्वारा दिए गए परिवाद की सरकार में सुनवाई हो।अदालत ने आदेश में कहा कि मुख्य सचिव इस एसोसिएशन के सभी अधिकारियों के साथ 04.09.2025 तक सुनवाई करे और 30 दिन के भीतर मामले में निर्णय दे।

गौरतलब है कि भारतीय रेल्वे में अनुसूचित जनजाति की एसोसिएशन की कोटा ज़ोन की

■ इस मामले में हाईकोर्ट के समक्ष दायर याचिका में कहा गया कि एसोसिएशन के अधिकारी “ट्राइबल” महानायक बिरसा मुंडा द्वारा, अनुसूचित जनजाति के हकों के लिए किए गए संघर्ष का भरपूर सम्मान करते हैं, परन्तु जिस जोर-जबर्ददस्ती और अनाधिकृत तरीके से उनकी मूर्ति स्थापित की गई, उससे केवल अनुसूचित जाति की भावनाओं को आहत करने की कोशिश की गई है।

■ याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 2022 में एसोसिएशन का चुनाव हार चुके एक गुट ने लोकसभा अध्यक्ष, ओम बिड़ला, के ओ.एस.डी. के साथ मिलकर अनाधिकृत तरीके से मूर्ति लगाने का कृत्य किया।

■ याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एफ.आई.आर. भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन, राजनैतिक दबाव के चलते एफ.आर. लगाकर मामले को ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया।

ईकाई ने हाईकोर्ट में रिट याचिका इसलिए दायर की थी क्योंकि पिछले वर्ष लोकसभा अध्यक्ष, ओम बिड़ला, के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (ओ.एस.डी.) ने एसोसिएशन को आवंटित

भवन में जबरदस्ती घूसकर, डॉ. भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के सामने ही अनाधिकृत, अवैध तरीके से झारखण्ड प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के महानायक, बिरसा मुंडा, की मूर्ति का

लोकार्पण किया, और अनुसूचित जाति के सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई।

याचिकाकर्ता के वकील सतीश पचौरी का कहना है कि वे बिरसा मुंडा के अनुसूचित

विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक 28 को

जयपुर, 26 अगस्त। सोलहवीं राजस्थान विधान सभा के चतुर्थ सत्र की बैठकें 1 सितम्बर से आरंभ होंगी। इससे पहले विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने, 28 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे विधान सभा में अपने कक्ष में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान, बसपा के

■ विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने यह परम्परा शुरू की थी।

मनोज कुमार, भारत आदिवासी पार्टी के थावर चन्द और रालोद के डॉ. सुभाष गर्ग को आमंत्रित किया गया है।

देवनानी ने विधान सभा अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद लोकसभा की तर्ज पर विधान सभा में भी सर्वदलीय बैठक बुलाये जाने का निर्णय लिया था। राजस्थान विधान सभा में पहली बार सोलहवीं विधान सभा से आरंभ हुई यह सर्वदलीय बैठक चौथी बार हो रही है।

एससीओ समिट में मोदी और पुतिन का स्वागत खुद करेगें जिनपिंग

शी इस कदम से ट्रंप को कड़ा मैसेज देना चाहते हैं कि टैरिफ वॉर में “ग्लोबल साउथ” एकजुट है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 26 अगस्त। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा ब्रिक्स देशों और अन्य साझेदारों पर टैरिफ युद्ध थोपने की पृष्ठभूमि में, ग्लोबल साउथ की एकजुटता का संदेश देने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन, चीन में होने जा रहे शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया जाएगा। यह कदम वांशिंगटन को एक सूक्ष्म किंतु स्पष्ट संदेश देने के रूप में देखा जा रहा है।

शी जिनपिंग अगले सप्ताह चीन में एक क्षेत्रीय सुरक्षा मंच पर 20 से अधिक विश्व नेताओं को इकट्ठा करेंगे, जिससे न केवल ट्रंप के समय ग्लोबल साउथ की शक्ति का प्रदर्शन होगा, बल्कि प्रतिबंधों से जुझ रहे रूस को एक और कूटनीतिक जीत पाने में मदद मिलेगी।

पुतिन और मोदी के अलावा, मध्य एशिया, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के नेताओं को भी

■ चीन में हो रहे तियानजिन समिट में शामिल होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को चीन जा रहे हैं। 7 सालों में उनकी यह पहली चीन यात्रा है और भारत और चीन के बीच गंभीर सीमा विवाद को देखते हुए भी यह यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

■ चीन भी चाहता है कि भारत अमेरिका के पाले में ना जाए क्योंकि एक स्वतंत्र तटस्थ भारत का चीन के साथ आना उसके लिए भी फायदेमंद हो सकता है।

आमंत्रित किया गया है। यह शिखर सम्मेलन भारत और चीन के बीच 2020 की यातक सीमा झड़पों के बाद तनाव कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है, क्योंकि अब भारत पर भी जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

पिछले साल कज़ान, रूस में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी मोदी, शी और पुतिन ने मंच साझा किया था, जबकि उस समय पश्चिमी नेताओं ने यूक्रेन युद्ध के चलते पुतिन से दूरी बना रखी थी। नई दिल्ली में रूसी दूतावास के अधिकारियों ने हाल ही में कहा कि मास्को को शी जिनपिंग और मोदी के साथ त्रिपक्षीय वार्ता की उम्मीद है।

चीनी राष्ट्रपति इस शिखर सम्मेलन को ऐसे से मंच के रूप में पेश करना चाहेंगे जो दिखाए कि अमेरिका के नेतृत्व से रहित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कैसी हो सकती है और यह भी जनवरी तक वाइट हाउस ने चीन, ईरान, रूस और अब भारत पर भी जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

चाइना-ग्लोबल साउथ प्रोजेक्ट के संपादक एरिक ओलेंडर ने कहा, जरा देखिए ब्रिक्स ने डॉनल्ड ट्रंप को कितना विचलित किया है – यही तो इन मंचों की मूल भूमिका है।

इस वर्ष का शिखर सम्मेलन एससीओ के 2001 में गठन के बाद से अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन होगा। चीनी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने इसे “अंतरराष्ट्रीय संबंधों की नई

प्रकार की संरचना में एक महत्वपूर्ण शक्ति” बताया।
हाल के वर्षों में भारत की नीति अमेरिका और इज़रायल के प्रति शुकाव के कारण एससीओ और ब्रिक्स के प्रति थोड़ी ठंडी पड़ी थी। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के घमकाने की नीति भारत तथा प्रधानमंत्री मोदी के प्रति असम्मानजनक रवैये ने भारत को इन मंचों की ओर फिर से आकर्षित किया है।

सुरक्षाकारणों से गठित एससीओ, जो कभी छह यूरोशियाई देशों का समूह था, अब 10 स्थायी सदस्य और 16 संवाद व पर्यवेक्षक देशों तक फैल चुका है। इसका ध्यान अब सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक और सैन्य सहयोग तक भी विस्तारित हो चुका है।
हालाँकि विश्लेषकों का मानना है कि एससीओ ने अब तक ठोस सहयोग के नतीजे नहीं दिए हैं, लेकिन चीन के लिए यह अमेरिका के विरुद्ध ग्लोबल साउथ की एकजुटता दिखाने का महत्वपूर्ण मंच बन चुका है।
कुछ विशेषज्ञ जो चीन को संदेह की दृष्टि से देखते हैं और अमेरिका भारत संबंध के समर्थक है उनका कहना है कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका ने 50% टैरिफ का नोटिफिकेशन जारी किया
नई दिल्ली, 26 अगस्त। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सामान पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने की योजना को एलान कर दिया है। यह वही टैरिफ है जिसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप पहले कर चुके हैं।
अमेरिकी होमलैंड सिक्यूरिटी विभाग ने एक ड्राफ्ट नोटिस जारी कर इसकी रूपरेखा पेश की। यह कदम ऐसे

■ नोटिस के अनुसार 27 अगस्त को रात 12.01 के बाद भारत के गोदामों से निकले माल पर यह टैरिफ लगेगा।

समय में उठाया जा रहा है, जब रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते की कोशिशें ठप पड़ती नजर आ रही हैं। नोटिस में साफ कहा गया है कि यह बढ़ा हुआ टैरिफ भारत के उन उत्पादों पर लागू होगा, जो 27 अगस्त, 2025 को सुबह 12:01 बजे (पूर्वी डेलाइट समय) के बाद खपत के लिए आयात (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

CMYK

● ● ● ● ●

⊕

● ● ● ● ●

⊕

● ● ● ● ●

⊕

● ● ● ● ●

CMYK

विचार बिन्दु

अन्याय को मिटाओ लेकिन अपने आप को मिटाकर नहीं। –फ्रेमचंद

न्याय की लंबी डगर: निचली अदालतों में तारीखों पर तारीखें

भारतीय न्यायपालिका केवल उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि न्याय के इन्हीं उच्च स्तरों से अधिकांश विधिक ज्ञान की शुरुआत होती है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि इन न्यायालयों में न्यायमूर्ति संवैधानिक सिद्धांतों की बारीकियों का अन्वेषण करते हैं, मौलिक अधिकारों के जटिल अंतर्संबंधों को व्याख्या करते हैं, और ऐसे निर्णय सुनाते हैं जो विधिक और लोकजगत दोनों पर अपनी छाप छोड़ते हैं। लेकिन यह भी सच है कि न्याय का असली संघर्ष निचली अदालत अर्थात 'ट्रायल कोर्ट' से शुरू होता है। भौंडभाड वाली मजिस्ट्रेटी अदालतों और कम रेशनी वाली सिविल अदालतों में न्याय की यह प्रक्रिया हमेशा एक मोहर और एक तारीख से शुरू होती है, तथा तारीख पर तारीख का किस्सा बन कर बरसों चलती रहती है। देश के अधिकांश मुकदमों के लिए ये निचली अदालतें प्रायः पहला संपर्क बिंदु होती हैं। लेकिन अनोखी बात यह है कि यह व्यवस्था इस तरह से है कि एक भी न्यायाधीश किसी मामले की शुरुआत से अंत तक सुनवाई नहीं कर पाता है। उनका तबला होता रहता है। न्याय में अत्यधिक देरी भारतीय न्यायिक प्रशासन की सबसे बुनियादी समस्याओं में से एक है। लेकिन उससे निबटने के लिए ट्रायल कोर्ट के बारे में देश में विश्वसनीय, व्यापक और मानकीकृत आंकड़ों का भी अभाव है। जैसे भारत को कितने न्यायाधीशों की जरूरत है? जाकरा लोग कहते हैं कि न्याय के न्यायिक आंकड़े न केवल खराब हैं, बल्कि वे संरचनात्मक रूप से भी भ्रामक हैं। इसका प्रमाण न्यायिक पारदर्शिता की एक महत्वपूर्ण पहल राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) है, जिसकी कार्यप्रणाली की ओलोनचनएंग होती रहती है। जैसे उसके आंकड़ों में तो मिस्ट के प्रक्रियात्मक आदेश से निपटारा एए मामले को भी पूरी सुनवाई के बाद समाप्त हुए मामले के बराबर गिना जाता है। आलोचक कहते हैं कि न्याय विभाग का डेटा विंग ऐसे अधिकारियों से भरप पड़ा है जिनकी न तो कोई न्यायिक पृष्ठभूमि है और न ही अनुभवजन्य विशेषज्ञता है और न न्यायिक सूचना विज्ञान का कोई औपचारिक प्रशिक्षण।

भारत की न्याय व्यवस्था पर जब भी चर्चा होती है तो सबसे बड़ा आरोप उस पर यही लगता है कि यहाँ न्याय देर से मिलता है, और कई बार तो इतनी देर से मिलता है कि उसका अर्थ ही बदल जाता है। आम नागरिक की अदालतों के प्रति सबसे बड़ी शिकायत यही है कि हर सुनवाई पर तारीख पर तारीख मिलती है, और अंतिम फैसला आने में बरसों बीत जाते हैं। निचली अदालतें देश की न्याय व्यवस्था की नींव हैं और उन्हीं के भरोसे आम आदमी न्याय पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाता है। न्याय मिलने में लंबे विलंब के दुष्परिणाम से भी सभी वाकिफ़ हैं?

फैसलों में देरी का कारण लंबित मामलों का बोझ बनाया जाता है। भारत की अदालतों में लटके पड़े मामलों की संख्या चौकाने वाली है। विभिन्न विधिक संगठनों की रिपोर्टें बार-बार चेतावनी देती रही हैं कि देशभर की अदालतों में करोड़ों मामले लंबित हैं। इनमें से लगभग 7० प्रतिशत से अधिक निचली अदालतों में अटक हुए हैं। कारण साफ़ है—केवल सीमित संख्या में जज और कर्मचारी हैं, जबकि मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। भारत में औसतन प्रति दस लाख आबादी पर केवल 2० न्यायाधीश उपलब्ध हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय मानक इसके कई गुना अधिक का सुझाव देता है। यानी, जजों की संख्या मुकदमों के बोझ के हिसाब से बेहद कम है। जब एक जज को रोजाना दर्जनों मुकदमों की सुनवाई करनी पड़ती है, तो अनिवार्य रूप से अधिकांश मामलों में केवल अगली तारीख देना ही संभव हो पाता है। भारतीय न्याय प्रणाली में प्रक्रियागत जटिलताएँ भी कम नहीं हैं। भारतीय दंड संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता जैसे कानूनों में प्रक्रियाएं इतनी जटिल और लंबी हैं कि उनका पालन करने में ही कई बार वर्षों खप जाते हैं। हालांकि इन कानूनों में बदलाव लाये गये हैं किन्तु उनका असर होने लगा हो ऐसा संकेत कहीं से नहीं मिल रहा है। गवाहों की पेशी, सबूतों का संग्रह, पुलिस रिपोर्ट, सरकारी विभागों से अनुमति या कागजात, विशेषज्ञ राय और अपील की प्रक्रिया—ये सब मिलकर एक मुकदमे को लंबा खींच देते हैं। सिविल मामलों में तो स्थिति और भी विकट है। ज़मीन—यजदाद, पारिवारिक विवाद, या अनुबंधों से जुड़े मामलों में बार-बार दस्तावेजों की मांग, गवाहों की अनुपस्थिति

और अपील की अंतहीन श्रृंखला न्याय की गति को और धीमा कर देती है। न्याय प्रक्रिया में देरी के लिए वकीलों और पक्षकारों की भूमिका को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। कई बार देरी का बड़ा कारण वकीलों और पक्षकारों का रवैया भी होता है। पक्षकार जानबूझकर सुनवाई टालने की कोशिश करते हैं ताकि मामला लंबा िखें और सामने पाने को थका दिया जाए। कई वकील भी तारीख पर तारीख लेने की नीति अपनाते हैं, क्योंकि लंबा मुकदमा उनके लिए आर्थिक रूप से लाभकारी साबित होता है। इस अतिरिक्त, गवाहों की अनुपस्थिति या पुलिस द्वाा समय पर चार्जशीट दाखिल न करना भी मामलों को आगे बढ़ने से रोक देता है। कई बार गवाहों को घमकाने या उन्हें मैनेज करने के मामले भी सामने आते हैं, वे पलट जाते हैं या पेश ही नहीं होते। ऐसे में अदालत को मजबूर होकर अगली तारीख देनी पड़ती है।

जानकार लोग देरी के लिए न्याय प्रणाली में तकनीकी ढांचे की कमी को भी इंगित करते हैं। आज जब डिजिटल क्रांति हर क्षेत्र में पहुंच चुकी है, तब भी निचली अदालतों की कार्यप्रणाली पूरी तरह तकनीकी रूप से आधुनिक नहीं हो सकी है। ई-कोर्ट और वर्चुअल हियरिंग की पहल उच्च न्यायालयों में तो हुई है, लेकिन यह अभी पूरी तरह ज़मीनी स्तर या निचली अदालतों तक नहीं पहुंची है। निचली अदालतों में कंप्यूटर, इंटरनेट और प्रशिक्षित कर्मचारियों की भारी कमी है। नतीजतन, फाइलें ढूँढ़ने, कागजात तैयार करने और आदेश दर्ज करने में अनावश्यक विलंब होता है।

कहा जाता है कि भारत में सबसे अधिक मुकदमों सरकार की तरफ से दर्ज होते हैं या गलत सरकारी निर्णयों के कारण दर्ज होते हैं इसलिए अदालतों में मुकदमों की इतनी अधिकता नज़र आती है। अदालतों में लंबित मुकदमों का बड़ा हिस्सा सरकार बनाम नागरिक वाले मामले होते हैं। कर, ज़मीन अधिग्रहण, सेवा विवाद, या अन्य प्रशासनिक निर्णयों के खिलाफ नागरिक अदालतों का रुख करते हैं। सरकार अपील दर अपील करती रहती है, जिससे मुकदमे वर्षों तक चल पड़ते हैं। निचली अदालतों में सरकारी वकीलों की अनुपस्थिति या उनकी तैयारी की कमी भी देरी को बढ़ाती है। सरकारी वकीलों की तैयारी की कमी की टिप्पणियाँ अदालती फैसलों में भी आती रहती हैं। न्यायिक संस्कृति और मानसिकता की दृष्टि से देखें तो भारतीय न्याय व्यवस्था में यह मानसिकता अब भी गहरी है कि "सभी पक्षों को पूरा अवसर मिलना चाहिए।" यह सिद्धांत सही है, लेकिन कई बार इसी के नाम पर बार-बार सुनवाई टाल दी जाती है। पश्चिमी देशों में मामलों की समयबद्ध सुनवाई होती है और अदालतें एक निश्चित समयसीमा में फैसला देने को बाध्य होती हैं। भारत में ऐसी सख्ती का अभाव है।

न्याय में देरी के दुष्परिणाम पर कम ही विचार हुआ है। न्याय अर्थहीन हो जाता है जब फैसला आने में बीस-बीस साल लग जाते हैं। तो कई बार जब पीडित पक्ष ही जीवित नहीं रहता है तब फैसला केवल कागजी महत्व का रह जाता है। इसीलिए लोग अदालतों से निराश होकर न्याय के लिए अन्य रास्ते अपनाने लगते हैं। यह लोकतंत्र और विधि के शासन के लिए खतरनाक होता है। लंबी मुकदमेबाजी गरीब और मध्यम वर्ग को आर्थिक रूप से तोड़ देती है। वकीलों की फीस, तारीख पर आने-जाने का खर्च और समय की बर्बादी लोगों को हतोत्साहित करती है जब मामलों का निपटारा देर से होता है, तो अपराधियों को छूट मिल जाती है। गवाह थक जाते हैं, सबूत कमजोर पड़ जाते हैं और दोषी बरी हो जाते हैं। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए बहुआयामी सुधार आवश्यक हैं। आबादी और मुकदमों के अनुपात में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाने की जरूरत है। तकनीकी सशक्तिकरण के लिए निचली अदालतों में ई-फाइलिंग और वर्चुअल हियरिंग को व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए उन्हें रिडिजिटल बनाया जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा हर प्रकार के मुकदमे के लिए एक निश्चित समय सीमा तय होनी चाहिए, ताकि तारीख पर तारीख देने की प्रवृत्ति खत्म हो। सरकार को हमेशा अपील करो की नीति छोड़नी चाहिए। केवल गंभीर और महत्वपूर्ण मामलों में ही अपील की रिप्रा। छोटे-मोटे विवादों को अदालत में लाने के बजाय लोक अदालत, मध्यस्थता और पंचायती व्यवस्था से सुलझाया जाने को बढ़ावा देना भी आवश्यक है। जानबूझकर मुकदमे लटकाने वालों पर जुर्माना लगाने की व्यवस्था की भी अनेक लोग सिफ़ारिश करते हैं। गवाहों को सुरक्षित और सहज वातावरण देना भी जरूरी है ताकि वे समय पर आकर अदालत में गवाही दे सकें।

तारीख पर तारीख का दर्द केवल किसी प्रकृति संवाद की सच्चाई नहीं है, बल्कि भारत के करोड़ों नागरिकों का जीता-जागता अनुभव है। न्याय में यह विलंब लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर करता है। न्यायपालिका को अब ऐसे ठोस कदम उठाने होंगे जिससे कि हर नागरिक को समय पर और निष्पक्ष न्याय मिल सके। न्याय देर से मिलना, न्याय न मिलने के बराबर है। निचली अदालतों में लंबित मामलों के बोझ और तारीख पर तारीख की संस्कृति को खत्म करना ही होगा। यही सच्चे लोकतंत्र और विधि के शासन की कसौटी है।

—अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)



डॉ. जे.के. गर्ग

गणेश में गण का अर्थ है वर्ग और समूह और ईश का अर्थ है स्वामी अर्थात जो समस्त जीव जगत के ईश हैं वहीं देवों के देव भगवान गणेश ही हैं। इसलिए उन्हें गणाध्यक्ष, लोकनायक गणपति के नाम से भी जाना जाता है। गणेशजी की चार भुजाएं चारों दिशाओं में सर्वव्यापकता की प्रतीक हैं। शिव मानस पूजा में श्री गणेश को प्रणव (३५) कहा गया है। इस एकाक्षर (३५ ब्रह्म में ऊपर वाला भाग गणेश का मस्तक, नीचे का भाग उदर, चंद्रबिंदु लङ्घ और मात्रा सूँड है)। विघ्नहर्ता गणेशजी की व्याख्या करने से स्पष्ट होता है कि गज दो व्यंजनों से यानि ग एवं ज से बना है, यहाँ अक्षर जन्म और उद्गम का परिचायक है वहीं ग गति और गन्तव्य का प्रतीक है। निसंदेह हमें गज से जीवन की उत्पत्ति और अंत का संदेश मिलता है यानि हमारे नखर शरीर को जहाँ से आया है वहीं पर वापस जाना है। निसंदेह जहाँ जन्म है वहाँ म्रत्यु भी है। सच्चाई तो यही है कि विनायक गणेशजी के शरीर की शारीरिक रचना के भीतर भोले शंकर शिवजी की सूक्ष्म सोस चिह्नित है, भगवान शिव ने गणेशजी के अंदर न्यायप्रिय, योग्य, कुशल एवं सशक्त शासक के समस्त गुणों के साथ उनके अंदर देवों के सम्पूर्ण गुण भी समाहित किये हैं।

गणेशजी की मूर्ति का विसर्जन क्यों किया जाता है ?

भाद्र शुक्ल चतुर्थी को गणेशजी की मूर्ति की स्थापना ढोल-नगाड़े के साथ घरों में जाती है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से अगले 1० दिन के बाद देश के विभिन्न प्रान्तों में गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, अगले बरस ७ जूल्दी आना के नारों के साथ गणपति की मूर्ति का विसर्जन हर्षोल्लास के साथ सरोवरों में किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से अगले 1० दिन तक गणपति को वेद

व्यास जी ने भागवत कथा सुनाई थी। गणेश जी की शर्त थी कि महर्षि एक क्षण के लिए भी कथावाचन में विश्राम ना लेंगे। यदि वे एक क्षण भी रुके, तो गणेश जी वहीं लिखना छोड़ देंगे। महर्षि ने उनकी बात मान ली और साथ में अपनी भी एक शर्त रख दी कि गणेश जी बिना समझे कुछ ना लिखेंगे। हर पंक्ति लिखने से पहले उन्हें उसका मर्म समझना होगा। गणेश जी ने उनकी बात मान ली। इस कथा को गणपति जी ने अपने दाँत से लिखा था। दस दिन तक लगातार कथा सुनाने के बाद वेद व्यास जी ने जब आँखें खोली तो पाया कि लगातार लिखते-लिखते गणेश जी के शरीर का तापमान काफी बढ़ गया है। महर्षि वेद व्यास जी ने गणेश जी को आदेश दिया कि वो तुरंत पास के कुंड में डुबकी लगा कर अपने आप को ठंडा कर लें। अतः इसी मान्यता के अनुसार गणेशजी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है।

हाथ में अंकुश: –गणेशजी का अंकुश हमें अपने लक्ष्य की ओर केन्द्रित रहते हुए हमेशा आगे बढ़ने का पाट पढ़ाता है। मनुष्य को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिये सतत प्रयास करते हुवे निरंतर आगे बढ़ना ही होगा। गणेशजी के हाथ में अंकुश हम सभी को भौतिकता से आध्यात्मिकता की तरफ चलने की शिक्रेषा भी देता है।

आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ : निसंविवाद रूप से जीवन में हमेशा जीत उन व्यक्तियों की होती है जो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करके आगे बढ़ते हैं। गणेशजी के आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ धारण करने के लिये अपने अपने लक्ष्य को दालने की क्षमता विकसीत करने की सीख देता है। अतः भगवान गणेशजी का आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ हमको उच्च कार्यक्षमता और अनुकूलन क्षमता प्राप्त करने की प्रेरणा देता है।

चूहे की सवारी: सभी देवी-देवता गणेशजी की बुद्धिमता के कायल हैं, तर्क-वितर्क में हर देवी-देवता गणेशजी से हार जाते थे। प्रत्येक समस्या के मूल में जाकर उसकी मीमांसा एवं विवेचना कर उसका तर्कसंगत हल खोजना उनकी विशेषता है इसलिए हर एक के मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि भगवान गणेशजी ने निकृष्ट माने जाने वाले चूहे (मृषक) को ही अपना वाहन क्यों चुना? इसी सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि चूहा भी तर्क-वितर्क में किसी से पीछे

नहीं रहता है, चूहे का काम हर किसी भी वस्तु को कुतर डालना है। जो भी वस्तु या चीज चूहे को दिखाई देती है, चूहे महाराज उसकी चीर फाड़ करके उसके प्रत्येक अंगो का विस्तृत विश्लेषण सा कर देते हैं, अतः संभवत गणेशजी ने चूहे के इन्हीं गुणों को देख कर चूहे को अपना वाहन चुना होगा। गणेशजी की चूहे की सवारी के बारे में यह भी कहा जाता है कि जैसे चूहे को इच्छा कभी पुरी नहीं होती, उसे कितना मिले हमेशा खाता रहता है वैसे ही मनुष्य की इच्छायें भी कितना भी मिले कभी पुरी नहीं होती क्योंकि लोभी आदमी का लालच कभी भी नहीं खत्म होता है। गणेश हमेशा चूहे की सवारी करते हैं इसका अर्थ है कि बेकाबू इच्छायें हमेशा विध्वंस का कारण बनती हैं। इनको काबू में रखते हुए इन पर राज करो, न कि इन इच्छाओं के मुताबिक खुद को उनमें लिप्त हो जा हो क्योंकि मनुष्य की इच्छायें और कामनाएं कभी भी पुरी नहीं होती हैं वरना आदमी इच्छाओं के मकड़ जाल में फंस कर असंतुष्ट तनावग्रस्त और दुखी रह कर अपने जीवन को बर्बादी के कगार पर ले आता है। अतः निसंदेह गणेशजी की चूहे की सवारी इन्सान की कभी भी पुरी नहीं होने वाली इच्छाओं का परिचायक है।

खड़े होने का भाव: गणेशजी की यह अवस्था बताती है कि दुनिया में रहते हुए मनुष्य को सांसारिक कर्म भी करने जरूरी है। वस्तुतः इन सबमें एक संतुलन बनाये रखते हुए उसे अपने सभी अनुभवों को परे रखते हुए अपनी आत्मा से जुड़े रखना चाहिए और अपने जीवन को आध्यात्मिकता सेजोड़ कर अंतर मुखी बनाना चाहिए।

हाथी का सिर : इस कहावत से हम सभी परिचित हैं कि बड़ा सिर सरदार और बड़ा पांव गंवां का गणपति का बड़ा सिर खुशहाल जीवन जीने के लिये ईसान के अन्दर मौजूद असीमित बुद्धिमता का प्रतीक है, वहीं विनायक के बड़े कान अधिक ग्राह्यशक्ति के प्रतीक है। गजानन लंबोदर हैं क्योंकि समस्त चराचर सृष्टि उनके उदर में ही विचरती है। हम लोगों यह भी जानना चाहिए कि गणपति के बड़े कान उनकी सर्वाधिक ग्राह्य शक्ति को दर्शाती है गजकर्णक की लंबी नाक (सूंड) महा बुद्धित्व का प्रतीक है।

विनायक का एक दंत:- विनायक का एक दंत: यह बतलाता है कि अच्छाई और अच्छों को अपने पास



रक्खो वहीं बुराई और बुरों का साथ तुरंत छोड़ दो। गणेशजी के बाई तरफ का दांत टूटा है। इसका एक अर्थ यह भी है कि मनुष्य का दिल बाई और होता है, इसलिए बाई और भावनओं का उफान अधिक होता है, जबकि दाई और बुद्धीपरक होता है। बाई और का टूटा दांत इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य को हमेशा अपनी भावनाओं पर बुद्धि और विवेक से नियन्त्रण रखना चाहिए। छोटी आँखें: गणेशजी की छोटी-पैनी आँखें हमें सिखाती है कि हमें सूक्ष्म एवं तीक्ष्ण दृष्टि वाला बनना चाहिए। सफलता प्राप्ति के लिये आदमी को एकाग्र चित्त बन कर अपना ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखते हुए अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए और मन को इधर-उधर भटकने से रोकना चाहिए। बड़ा पेट: विघ्ननाशक गणेश जी का बड़ा पेट हमें सिखाता है कि मनुष्य को अच्छी-बुरी सभी बातों-भावों को समान भाव से ग्रहण करना चाहिए, उन्हें समान भाव से लेना चाहिए। दूसरे शब्दों में गणेशजी का बड़ा पेट मनुष्य को उदार आदतों का धनी बनने की सीख देता है। जीवन में कुछ बातों को पेट में पचा लेना चाहिए। धीरे और गम्भीर पुरुषों का समाज में सम्मान होता है।

क्यों सिर्फ माता पिता के चरणों में ही बसता है समस्त संसार?

एक बार देवता अनेकों आपदाओं में घिरे हुए थे, तब वे मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। देवताओं की बात सुनकर शिवजी के दोनों पुत्रों कार्तिकेय व गणेशजी ने शिवजी से

देवताओं की मदद करने की आज्ञा मांगी, तब भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जा सकेगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय तो अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। किन्तु गणेशजी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी गणेशजी को एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठें और अपने माता-पिता की सात बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए।

विघ्नहर्ता गणेश जी एक मुद्रा में कलिंग साप के फन के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। यह बुराई पर अच्छाई की जीत दर्शाता है। अपने इस स्वरूप में भगवान गणेश कलियुग के उन लोगों की सहायता करते हैं जो अपने अच्छे कर्मों के बावजूद, समस्याओं को झेल रहे हैं। अलिंग अपने इस स्वरूप में भगवान गणेश कलिंग नामक साप के फन के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। यह बुराई पर अच्छाई की विजय को दर्शाता। बुद्धि ऋद्धि सिद्धि सुख स्वास्थ्य सम्पन्नता को देने वाले देव देवों गणपति भगवान के श्री चरणों मे कोटि कोटि प्रणाम। 27 अगस्त 2025 को देश प्रथम पूज्य भगवान विनायक का पञ्चोत्सव हर्षोल्लास के साथ मना रहा है।

—डॉ. जे.के गर्ग,
पूर्व संयुक्त निदेशक कालेज शिक्षा जयपुर

मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल अजमेर में साहित्यिक महाकुंभ के चौदहवें संस्करण का समापन

साहित्यिक प्रतियोगिता में देशभर से 22 विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों से लगभग 250 प्रतिभागियों ने प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन किया

जयपुर/अजमेर। अजमेर स्थित मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल में चार दिवसीय साहित्यिक महाकुम्भ रजत जयंती स्मृति युवा विचारक सम्मेलन-2025 कार्यक्रम का समापन समारोह आयोजित हुआ। इस साहित्यिक प्रतियोगिता में देशभर से 22 विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों से लगभग 25० प्रतिभागियों ने रजत जयंती स्मृति अन्तर्विद्यालयीय हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता विचारवाणी, हिंदी सृजनात्मक स्वरचित काव्य पाठ प्रतियोगिता सृजन अभिव्यक्ति: मन की उड़ान, इंग्लिश एनैक्टमन्ट / ड्रामाटिक्स, मल्टी फॉर्मेट इंग्लिश डिबेट, इंग्लिश सृजनात्मक लेखन, सामान्य वि्वज जैसी विविध प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा और कौशलदा का प्रदर्शन किया।

कार्यक्रम में मेयो एल्युमनाई एसोसिएशन, जयपुर चैप्टर के अध्यक्ष एवं जनसंपर्क विशेषज्ञ, जगदीप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता और उपविजेताओं टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अनूठे कार्यक्रम को प्रसिद्ध शिक्षाविद् प्रणव मुखर्जी ने व्यूरेट किया। समापन समारोह पर मुख्य अतिथि जगदीप सिंह ने अपने संबोधन में विद्यालय की प्राचार्या, प्रबंधन तथा कार्यक्रम के संयोजकों



मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल अजमेर में रजत जयंती स्मृति युवा विचारक सम्मेलन-2०25 संपन्न हुआ।

के प्रति आभार प्रकट किया और कहा कि मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल सदैव उत्कृष्टता और मानवीय मूल्यों का प्रतीक रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल करियर की तैयारी नहीं है, यह जीवन की तैयारी है। सदैव जिज्ञासु और रचनात्मक बनें।

जॉन लेंनन का उदाहरण देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि चाहे आप पायलट बनें, इंजीनियर या उद्यमी बनें,

अपने भीतर की मानवीयता को कभी न छोएं। सदैव प्रसन्न रहें और जीवन को समझने का प्रयास करें।

इस चार दिवसीय प्रतियोगिताओं का परिणाम इस प्रकार रहा :-हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता का विजेता मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल अजमेर रहा। हिंदी सृजन-अभिव्यक्ति: मन की उड़ान प्रतियोगिता में बेस्ट डेलिगेशन अवॉर्ड सनबीम स्कूल, लहरतारा ने जीता। इंग्लिश एनैक्टमन्ट/ड्रामाटिक्स में

के विजेता मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल, अजमेर से जाह्नवी सोमानी और छवि सिंह रहे।

मल्टी फॉर्मेट अंग्रेजी डिबेट प्रतियोगिता में बेस्ट डेलिगेशन के साथ मेयो कॉलेज, अजमेर विजेता रहा। अंग्रेजी सृजनात्मक लेखन प्रतियोगिता में बेस्ट डेलिगेशन अवॉर्ड सनबीम स्कूल, लहरतारा ने जीता। इंग्लिश एनैक्टमन्ट/ड्रामाटिक्स में

■ वाद-विवाद, काव्य पाठ, ड्रामाटिक्स, सामान्य वि्वज आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ

■ समारोह में अतिथियों ने विभिन्न प्रतियोगितां के विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया

बेस्ट डेलिगेशन ट्रॉफी बिरला विद्या मंदिर, नैनीताल ने जीती। वहीं, सामान्य वि्वज में ओवरऑल बेस्ट डेलिगेशन में के सी पब्लिक स्कूल जम्पू विजेता रहा।

इस अवसर पर स्कूल की प्राचार्या नीति भल्ला सैनी ने सभी प्रतिभागी विद्यालयों को बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने संबोधन में आत्म-चिंतन के महत्व पर जोर दिया, जिससे हम खुद के भीतर ज्ञांक संके, विचार कर सकें और सभी प्रकार के कौशलों में कई गुना वृद्धि कर सकें।



पंडित अनिल शर्मा

मिथुन, शुक्र-कर्क, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में। आज भद्रा दिन 3:45 तक है। आज महागणपति चतुर्थी है। शाकों के अनुसार गणेश पूजन का श्रेष्ठ समय दिन 11:13 से दिन 1: 45 तक रहेगा। दिन 12:11 से दिन 1:45 तक वृश्चिक लग्न और भी श्रेष्ठ रहेगा। आज जैन संवत्सरी (चतुर्थी पक्ष) है। आज से गणेश महोत्सव आरम्भ होगा।
श्रेष्ठ चोचड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:18 तक, शुभ 1०:53 से 12:28 तक, चर 3:39 से 5:14 तक, लाभ 5:14 से सूर्यास्त तक।
राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 6:08, सूर्यास्त 6:49

राशिफल

बुधवार 27 अगस्त, 2025

भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्थी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत् 2०82, चित्रा नक्षत्र गुरुवार प्रातः 8:44 तक, शुभ योग दिन 12:34 तक, विष्टि करण दिन 3:45 तक, चन्द्रमा सायं 7:21 से तुला राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-कन्या, बुध-कर्क, गुरु-मिथुन, शुक्र-कर्क, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में। आज भद्रा दिन 3:45 तक है। आज महागणपति चतुर्थी है। शाकों के अनुसार गणेश पूजन का श्रेष्ठ समय दिन 11:13 से दिन 1: 45 तक रहेगा। दिन 12:11 से दिन 1:45 तक वृश्चिक लग्न और भी श्रेष्ठ रहेगा। आज जैन संवत्सरी (चतुर्थी पक्ष) है। आज से गणेश महोत्सव आरम्भ होगा।
श्रेष्ठ चोचड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:18 तक, शुभ 1०:53 से 12:28 तक, चर 3:39 से 5:14 तक, लाभ 5:14 से सूर्यास्त तक।
राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 6:08, सूर्यास्त 6:49



मेष

परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। विवादित मामलों से राहत मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। धार्मिक-मांगलिक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है।



तुला

व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। नौकरपेशा व्यक्तियों को मानसिक तनाव बढ़ेगा। घर-परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।



वृष

परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।



वृश्चिक

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है।



मिथुन

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



धनु

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। नौकरपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



कर्क

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।



मकर

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटक हुए कार्य बनें लगेगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।



सिंह

आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए रखना व्यावसाय

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसान हितों के प्रति संवेदनशील प्रदेश में मांग अनुसार उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति एवं अतिरिक्त आपूर्ति की कार्यवाही जारी

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । राज्य सरकार और कृषि विभाग द्वारा किसानों को उर्वरकों की निबांध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। विशेष रूप से यूरिया और डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा उर्वरकों की दैनिक उपलब्धता पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। कम उपलब्धता और अधिक खपत वाले जिलों व ब्लॉकों को चिन्हित कर प्रदेश भर में प्राथमिकता के साथ पूर्ण पारदर्शिता से डीएपी व यूरिया का वितरण किया जा रहा है। उर्वरकों की कालाबाजारी व जमाखोरी को रोकने के लिए कृषि विभाग के अधिकारी प्रदेश भर में पूर्ण सतर्कता से कार्य कर रहे हैं।

राज्य सरकार द्वारा निरंतर केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर

प्रदेश की मांग अनुसार उर्वरकों की आपूर्ति करवाई जा रही है। राज्य के किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु खरीफ 2025 में अप्रैल से अगस्त तक भारत सरकार द्वारा आवंटित 8 लाख 82 हजार मैट्रिक टन यूरिया के विरुद्ध अब तक 8 लाख 23 हजार मैट्रिक टन की आपूर्ति की जा चुकी है। अगस्त माह की शेष अवधि में 59 हजार मैट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति राज्य सरकार द्वारा कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

माह अप्रैल से अगस्त तक भारत सरकार द्वारा आवंटित 4 लाख 75 हजार मैट्रिक टन डीएपी के विरुद्ध अब तक 3 लाख 59 मैट्रिक टन डीएपी की आपूर्ति की जा चुकी है, शेष 27 हजार मैट्रिक टन डीएपी की आपूर्ति प्रस्तावित है।

प्रदेश में वर्तमान में 1 लाख 86 हजार मैट्रिक टन यूरिया, 1 लाख 20 हजार मैट्रिक टन डीएपी, 0.81 लाख

■ **खरीफ 2025 में अप्रैल से अगस्त तक भारत सरकार द्वारा आवंटित 8 लाख 82 हजार मैट्रिक टन यूरिया के विरुद्ध अब तक 8 लाख 23 हजार मैट्रिक टन की आपूर्ति की जा चुकी है।**

■ **अगस्त माह की शेष अवधि में 59 हजार मैट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति राज्य सरकार द्वारा कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।**

मैट्रिक टन एनपीके एवं 1 लाख 93

हजार मैट्रिक टन एसएसपी उर्वरकों का स्टॉक उपलब्ध है। वर्तमान में गत वर्ष की तुलना में फॉस्फेटिक उर्वरकों का स्टॉक 1 लाख मैट्रिक टन अधिक है एवं आपूर्ति जारी है। यूरिया की लगभग 8000 मैट्रिक व डीएपी की 10 हजार 900 मैट्रिक उर्वरक रेल द्वारा परिवहन में है।

केंद्र सरकार की ओर से यूरिया, डीएपी एवं अन्य उर्वरकों का राज्य को माहवार जिलेवार आपूर्ति योजना तैयार कर प्रदेश में उर्वरकों को वितरण कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त आवंटन एवं जिलों की मांग के अनुसार जिलेवार आपूर्ति योजना तैयार कर प्रदेश में उर्वरकों को वितरण कराया जाता है।

राज्य सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध हो कर कार्य कर रही है और यह सुनिश्चित करने हेतु हर संभव प्रयास कर रही है कि खेती-किसानी में किसी प्रकार की बाधा न आए। यूरिया एवं डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता के साथ-साथ उनकी

उचित कीमत पर आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है।

कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड में अंकित सिफारिश के अनुसार ही उर्वरकों के उपयोग हेतु प्रेरित करने, उर्वरकों का समान रूप से पारदर्शिता के साथ वितरण कराने और उर्वरक वितरण में अनियमितता बरतने वाले विक्रेताओं, जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हेतु समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

विभाग द्वारा समस्त किसानों को समान रूप से उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के लिए कृषकों को पंक्तिबद्ध किया जाकर उर्वरकों का वितरण प्रशासन के सहयोग एवं विभागियों कार्मिकों की देख-रेख में किया जा रहा है। राज्य में सरसों फसल की अग्रिम बुवाई करने वाले जिलों में किसानों द्वारा डीएपी का क्रय कर अग्रिम भण्डारण किया जा रहा है।

‘भजनलाल सरकार ने 80-90 प्रतिशत बजट घोषणाओं को क्रियान्वित किया’

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी ने मंगलवार को जयपुर में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संवाद में सांसद एवं विधायकों को केन्द्र और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों को अधिक से अधिक आमजन तक पहुंचाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने का आग्रह किया है।

चतुर्वेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अपने बजट की 80 से 90 प्रतिशत से अधिक बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन किया है। राम जलसेतु लिंक परियोजना और यमुना जल समझौते को मूर्त रूप प्रदान किया। वहीं, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय में ईआरसीपी की योजनाओं पर गंभीरता से कार्य नहीं हुआ और केवल राजनीति हुई। उस समय जब तत्कालीन जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जल परियोजनाओं पर बैठक लेने आए तो पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री बैठक से नदारद रहे। चतुर्वेदी ने कहा कि राज्य सरकार ने हर क्षेत्र और हर वर्ग के विकास के लिए कार्य किया है। लगभग 75 हजार पदों पर सरकारी नियुक्तियां प्रदान की गईं। आने वाले कुछ दिनों में 15-20 हजार सरकारी भर्तियों की घोषणा होने वाली है। हमारी सरकार, पहली सरकार है जिन्होंने सरकारी भर्तियों का कैलेण्डर जारी किया है। उन्होंने कहा कि यूरिया और खाद की आपूर्ति प्रदेशभर में सुनिश्चित की जा रही है तथा इनकी कालाबाजारी को प्रभावी रूप से रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

नामांकन के बाद विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित हों : राज्यपाल शैक्षिक उत्कृष्टता के लिए निरंतर कार्य हो, ताकि राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बने : हरिभाऊ बागडे

जयपुर । राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कुलगुरुओं को व्यक्तिगत रूचि लेकर शैक्षिक उत्कृष्टता के लिए कार्य करने का आह्वान किया है। उन्होंने विश्वविद्यालयों में नामांकन के बाद विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने, इस हेतु अच्छे ढंग से पढ़ाने, रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों से उन्हें जोड़ने आदि के लिए भी कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने राजस्थान को उच्च शिक्षा में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में सुधार हो, नहीं तो उनके खिलाफ भी कड़े कदम उठाए जाएंगे।

राज्यपाल बागडे मंगलवार को राजभवन में विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विश्वविद्यालयों में नैक शिक्षा नीति लागू करने, विश्वविद्यालयों में नैक एंक्रिडिएशन की कार्यवाही पूर्ण करने, वहां उपलब्ध लैब, पुस्तकालय, खेल मैदानों और छात्रावास के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली।

उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों में एक समान प्रश्नपत्र और पाठ्यक्रम लागू किए जाने की व्यावहारिकता के बारे में भी सुझाव लिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के गोद लिए गानों को पिपलॉली पैटर्न पर विकसित किया जाए। वहां पर अच्छे छायादार पौधे, फल, प्राकृतिक खेती के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित कर कार्य किया जाए।

राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में शोध के अंतर्गत मौलिक दृष्टि रखे जाने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में पेंशन, वेतनमान आदि के लिए भी राज्य सरकार स्तर पर संवाद कर सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे।

जल जीवन मिशन के 900 करोड़ के टैंडर घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को राहत नहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने महेश जोशी की जमानत याचिका खारिज की

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े ईडी प्रकरण में आरोपी पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को राहत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में महेश जोशी की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश महेश जोशी की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिए। एकलपीठ ने गत 8 अगस्त को मामले में फैसला सुरक्षित रखा था।

इस मामले में ए.सी.बी. की 2 तथा सीबीआई की एक एफ.आई.आर. समेत कुल 4 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जिससे ईडी की ओर से चारों मामलों को संयुक्त तरीके से जांच जा रहा है। इस मामले में ईडी की ओर से अधिवक्ता अश्वय भारद्वाज ने हाईकोर्ट में बताया कि, पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में मंत्री जलदाय मंत्री रहे महेश जोशी ने इस जल जीवन मिशन घोटाले में मुख्य भूमिका निभाई है। अगर महेश जोशी, मंत्री के पद पर नहीं होते तो इस घोटाले को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। उन्होंने कहा कि, इस मामले में मुख्य दलाल संजय बडाय़ा, पदमचंद जैन, महेश जोशी व उनके पुत्र रोहित जोशी, मंगललाल सेनी समेत 18 लोगों की भूमिका संदिग्ध है। ईडी की ओर से कहा गया कि, इस मामले में संजय बडाय़ा ने पदमचंद जैन

- ईडी की ओर से अदालत में कहा गया कि, पदमचंद जैन और अन्य लोगों की फर्मों ने फर्जी “ईस्कॉन सर्टिफिकेट” पेश करके यह टैंडर हासिल किए थे
- ईडी का कहना था कि, इस 900 करोड़ के टैंडर में से 620 करोड़ रु. तो पूर्ववर्ती अशोक गहलोत की सरकार के समय ही रिलीज कर दिए थे, जबकि इन फर्मों का काम आंशिक हुआ था
- ईडी का कहना है कि, मामले में घोटाले की पूरी राशि 625 करोड़ रु. मानी जानी चाहिए, हालांकि उनके पास 5.50 करोड़ की घूस राशि के लेन-देन का पुख्ता सबूत है। अभी भी ई.डी. इस मामले में जांच कर रही है।

और पीपूष जैन को 900 करोड़ रु. का टैंडर दिलवाया। परंतु जल जीवन मिशन में टैंडर डालने के लिए सिर्फ वही कंपनियां भाग ले सकती थी, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत “ईस्कॉन इंटरनेशनल लि.” द्वारा मान्यता प्राप्त हो। गौरतलब यह है कि इस मामले में जिन कंपनियों को 900 करोड़ रु. तक के टैंडर दिए गए, उनमें से किसी के पास भी यह सर्टिफिकेट नहीं था। इन फर्मों ने फर्जी दस्तावेज और सर्टिफिकेट लगाकर यह टैंडर हासिल किए थे। ई.डी. की जांच में यह भी सामने आया कि, पीएचईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी पारितोष गुप्ता ने फर्जी सर्टिफिकेट की जांच करने हेतु “ईस्कॉन” को सत्यापन के लिए ई-मेल भेजा था। जिस पर “ईस्कॉन” की ओर

से जवाब दिया गया था कि उन्होंने इन कंपनियों को कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया, जिन्होंने राजस्थान में जल जीवन मिशन के टैंडरों में भाग लिया। जैसे ही तत्कालीन मंत्री महेश जोशी को इस बात का मालूम चला तो अधिकारी पारितोष गुप्ता का अन्यत्र स्थानांतरण कर दिया गया था।

ई.डी. की ओर अदालत में कहा गया कि, उनके पास कई अधिकारी-कर्मचारियों के बयान हैं कि, उन्हें तत्कालीन मंत्री महेश जोशी ने अनौपचारिक आदेश देकर देखे थे कि संजय बडाय़ा के कबे अनुसार काम करो, अन्यथा तबादला कर दिया जायेगा।

ईडी का कहना है कि फर्जी “ईस्कॉन सर्टिफिकेट” के आधार पर पदमचंद जैन और अन्य फर्मों को 900

करोड़ का टैंडर मिला। इसमें से पिछली अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में ही 625 करोड़ रु. की मंजूरी दी जा चुकी थी तथा 620 करोड़ रु. रिलीज कर दिए गए थे। जबकि इन फर्मों द्वारा आंशिक कार्य ही किया गया था।

ई.डी. का कहना है कि, इस 625 करोड़ रु. की राशि को ही घोटाले का मूल आधार माना जाए। ईडी की जांच में 5.5 करोड़ रु. की धांधली का स्पष्ट उजागर हुई है। इसमें से 3.3 करोड़ रु. संजय बडाय़ा ने बतौर कमीशन नकद लिया। शेष 2.1 करोड़ रु. का 50 प्रतिशत हिस्सा महेश जोशी के बेटे की कंपनी में दिया गया। बाकी बचे हुए 1.06 करोड़ रु. महेश जोशी के बेटे ने संपत्ति खरीदी।

ईडी की ओर से अधिवक्ता अश्वय भारद्वाज ने कहा कि महेश जोशी के बेटे की फर्म “शुभ मोलम” में 50 लाख रुपए का लेनदेन किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से इस राशि को लौटाना भी बताया जा रहा है तो राशि लौटाने से अपराध की गंभीरता कम नहीं होती है। वहीं महेश जोशी की ओर से जमानत याचिका में अदालत को बताया कि प्रकरण में उसे फंसाया गया है। प्रकरण को लेकर एसीबी ने दर्ज मूल केस में याचिकाकर्ता का नाम नहीं है। याचिकाकर्ता को एक साल पहले नोटिस दिया गया। इसके बाद बिना कोई परिस्थिति बदले उसे गत अप्रैल माह में

गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा ईडी याचिकाकर्ता पर 2.01 करोड़ रुपए का आरोप लगा रही है, जबकि इसे लेकर ईडी के पास कोई साक्ष्य नहीं है और परिवारी यह राशि कहा से लाया, उसका भी उल्लेख नहीं है। इसके अलावा ईडी ने अपनी रिपोर्ट में बेटे की फर्म में 50 लाख रुपए का लेनदेन बता रही है। यह राशि बेटे की कंपनी ने लोन के तौर पर ली थी और उसे लौटाया भी जा चुका है। वहीं इस राशि को लेकर सिविल केस भी लंबित चल रहा है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाए।

हालांकि जिरह के दौरान यह स्पष्ट हो गया था कि संजय बडाय़ा के कहने पर ही पदमचंद जैन व अन्य कंपनियों ने महेश जोशी के बेटे की फर्म में 50 लाख रु. डाले थे। ईडी ने जब उनसे पूछा कि क्या वह महेश जोशी के बेटे को जानते हैं अथवा पहचानते हैं तो उन्होंने इनकार कर दिया। इस पर ईडी की ओर से कहा गया कि, यह घूस की राशि है, ऐसे अनजान लोगों को ऋण कौन देता है। याचिकाकर्ता और उसके बेटे ने विभाग की टैंडर प्रक्रिया में रिखत प्राप्त की है। यदि आरोपी को जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए उसकी जमानत याचिका को खारिज किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी महेश जोशी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

जयपुर जिले से 4905 वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा तीर्थ यात्रा का अवसर

जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने निकाली ऑनलाइन लॉटरी

जयपुर । राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2025 के तहत जयपुर जिले के 4 हजार 905 वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा का अवसर मिलेगा। मंगलवार को देवस्थान मंत्री जोगाराम कुमावत की मौजूदगी में जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम

- देवस्थान मंत्री जोगाराम कुमावत सहित अन्य जनप्रतिनिधि रहे मौजूद**
- 526 सफल आवेदक हवाई जहाज से तथा 4379 रेल से करेंगे तीर्थ यात्रा**



देवस्थान मंत्री जोगाराम कुमावत की मौजूदगी में जयपुर जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2025 की ऑनलाइन लॉटरी निकालकर सफल आवेदकों की घोषणा की।

526 यात्री हवाई मार्ग से काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा करेंगे, जबकि 4 हजार 379 यात्री रेल मार्ग से विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करेंगे। योजना के तहत जयपुर जिले के कुल आवेदन 11 हजार 378 एवं कुल यात्री 18 हजार 423 प्राप्त हुए।

उन्होंने बताया कि रेल यात्रा के लिए चयनित वरिष्ठ नागरिकों को हरिद्वार-त्र्यंघ्रिवेनश-अयोध्या-वाराणसी-सारनाथ, समेदशिवर-पावापुरी-वाराणसी-सारनाथ, मथुरा-वृंदावन-बरसाना-आगरा-अयोध्या, द्वारकापुरी-नागेश्वर-सोमनाथ, तिरुपति-पदमावति, कामाख्या-गुवाहाटी, गंगासागर-कोलकाता, जगन्नाथपुरी-कोणार्क, रामेश्वरम-मदुरई, वैष्णो देवी-अमृतसर-वाघा बोर्डर, गोवा के मंदिर एवं अन्य स्थल चर्च आदि, महाकालेश्वर-उज्जैन-ओं नगरे श्वर-त्रयम्बावेऽश्वर-घृष्णेश्वर-ऐलोरा, बिहार शरीफ, पटनासाहिब पटनाबिहार, श्री हजुर साहिब नंदेड़ जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों का दर्शन करवाया जाएगा।

इस अवसर पर देवस्थान मंत्री जोगाराम कुमावत ने बताया कि राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना वरिष्ठ नागरिकों को

धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर देकर उनके जीवन में आध्यात्मिक संतोष और मानसिक शांति का संचार करती है। यह यात्रा ना केवल व्यक्तिगत अनुभव है बल्कि सामूहिकता, मेल-जोल और सामाजिक संबंधों को भी सुदृढ़ करती है।

उन्होंने बताया कि 70 वर्ष से अधिक आयु के यात्री अपने साथ एक अटेंडेंट ले जा सकते हैं। साथ ही, यदि पति-पत्नी में से एक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक और दूसरे की आयु 58 वर्ष है तो दोनों को एक साथ यात्रा की अनुमति है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। इसके लिए प्रत्येक दल के साथ चिकित्सा स्टाफ, सुरक्षा कर्मी और सरकारी कर्मचारी यात्रा करेंगे।

राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, विधायक चंद्रप्रकाश आख्या, जीवाराम चौधरी, अशोक कोठारी, प्रियंका चौधरी जिला कलक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) देवेन्द्र कुमार जैन और देवस्थान विभाग के अतिरिक्त निदेशक रतनलाल योगी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

‘दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के आवेदन ऑनलाइन प्रोसेस करें’

जयपुर । प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित दिव्यांगता प्रमाण-पत्र को आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किए जाने के निर्देश जारी किये गये। बैठक में मौसमी बीमारियों सहित विषयों पर भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. अमित कुमार यादव, अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम डॉ.टी. शुभमंगला, निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने मौसमी बीमारियों, टीबी मुक्त अभियान, एनसीडी गतिविधियों, यूडीआईडी कार्ड, मेडिको लीगल केस, अपंगीकृत चिकित्सक एवं प्रयोगशालाओं के विकसक की गयी कार्यवाहियों, आरजीएचएस व आयुष्मान योजना, राज हैथ्य पोर्टल पर चिकित्सा संस्थानों व स्वास्थ्यकार्मिकों की मैपिंग कार्य के दिशा-निर्देश दिये।

मंत्री अविनाश गहलोत ने की समाज कल्याण से जुड़े कार्यों की समीक्षा बजट घोषणाओं की शत प्रतिशत क्रियान्विति करने के निर्देश दिए

जयपुर । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बजट घोषणाओं की क्रियान्विति शत-प्रतिशत होना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि घोषणाओं के बेहतर क्रियान्वयन से ही आमजन को लाभ पहुंच सकता है। गहलोत मंगलवार को मुख्यालय के अंबेडकर भवन के सभागार में आयोजित विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने बजट घोषणा वर्ष 24-25 एवं 25-26 की बिंदुवार प्रगति रिपोर्ट ली और लंबित कार्यों के लिए विशेष कार्ययोजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए। इस दौरान विधानसभा में विशेष योग्यजन, पेंशन, छात्रवृत्ति, महिला कल्याण, छात्रावास सहित अन्य विषयों से जुड़े प्रश्नों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।

सामाजिक न्याय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा समाज के वंचित तबके को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभान्वित करना है। उन्होंने बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के बचिक्त भौतिक सत्यापन की स्थिति, छात्रवृत्ति की वित्तीय भौतिक प्रगति, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में चयनित अभ्यर्थियों में से कोचिंग संस्थानों में ज्वाइन किए गए



सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने मंगलवार को अधिकारियों की बैठक लेकर विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति जानी।

निर्देश भी दिए। निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आशीष मोदी ने कहा कि वर्ष 2024-25 की कुल 26 बजट घोषणाओं में से 13 पूर्ण हो चुकी है, 10 प्रगतिरत हैं। जबकि 3 प्रक्रियाधीन है। वहीं वर्ष 25-26 की 15 घोषणाओं में से 8 पूर्ण हो चुकी है, 4 प्रगतिरत हैं, जबकि 3 प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि सभी घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है।बैठक में आयुक्त निदेशालय विशेष योग्यजन केसर लाल मोना, वित्तीय सलाहकार अंजु सिंह, निजी सचिव रोहित पटेल, अतिरिक्त निदेशक हरिसिंह मोना, रीना शर्मा, सुण्डरायण सीना, अशोक निगिंड, अरविन्द कुमार मीना, अनुजा निगिंड के वीरेन्द्र सिंह सहित बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्यजन विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

‘कांग्रेस कमीशन देखती थी, हम ‘‘सबका विकास’’ में विश्वास रखते हैं’

मुख्यमंत्री भजनलाल ने सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष संवाद में विकसित राजस्थान की रूपरेखा पर चर्चा की



विकास के संकल्प पर सांसद-विधायक संवाद

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांसद-विधायक संवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन मंगलवार को नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर-सिरोही, पाली, बीकानेर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, अजमेर और दौसा के जनप्रतिनिधियों और जिला अध्यक्षों से संवाद किया।

जयपुर, 26 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांसद-विधायक संवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर-सिरोही, पाली, बीकानेर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, अजमेर और दौसा संसदीय क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों और भाजपा जिला अध्यक्षों के साथ प्रदेश के विकास पर संवाद किया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विकसित राजस्थान 2047 की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए कहा कि जन आकांक्षाएं राज्य सरकार के विजन का केन्द्र बिन्दु हैं। हमारी सरकार ने बजट में सभी 200

■ मुख्यमंत्री ने कहा, कि शेखावाटी की हवेलियां हमारी विरासत हैं। यदि हम इनका संरक्षण व संवर्धन कर टूरिस्ट सर्किट के माध्यम से विकास करें तो पर्यटकों का ठहराव बढ़ेगा, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा व स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।

विधानसभा क्षेत्रों के लिए बिना किसी भेदभाव के बजट का प्रावधान किया है। हमारी सरकार सबका साथ-सबका विकास में विश्वास रखती है, जबकि पिछली कांग्रेस सरकार कमीशन के लिए काम करती थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियां हमारी विरासत हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कहना है कि

विरासत और विकास दोनों साथ चलने चाहिए। उन्होंने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र में घरेलू पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। यदि हम इन हवेलियों का संरक्षण और संवर्धन कर टूरिस्ट सर्किट के माध्यम से इनका विकास करें तो इससे पर्यटकों का ठहराव बढ़ेगा। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर लोगों को

रोजगार मिलेगा।

शर्मा ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के अधिक से अधिक किसानों को केन्द्र एवं राज्य की योजनाओं से लाभान्वित करें।

इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश के 17 जिलों के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना (ईआरसीपी) को धरातल पर शुरू किया। साथ ही, शेखावाटी क्षेत्र में पानी की उपलब्धता के लिए यमुना जल समझौते को मूर्त रूप दिया है।

संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा कि आगामी विधानसभा सत्र के दौरान वे पूरी तैयारी कर सदन में होने वाली चर्चा में भाग लें।

एससीओ समिट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

महत्वपूर्ण रक्षा मुद्दों को संबोधित करने में एससीओ विफल रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव इस मंच पर भी झलकता है। जून में हुए एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने हिंदू पर्यटकों पर हमले का जिक्र न होने पर आपत्ति जताई, जिससे संयुक्त बयान जारी नहीं हो सका। भारत ने ईरान पर इजरायली हमले की निंदा करने वाले एससीओ बयान में भी शामिल होने से इनकार कर दिया था। हालांकि भारत-चीन संबंधों में हाल ही में आई नरमी और ट्रंप प्रशासन की ओर से भारत पर नए टैरिफ दबाव ने इस बार शी-मोदी बैठक से सकारात्मक उम्मीदें जगा दी हैं। एरिक ओलेंडर के अनुसार, “संभव है कि भारत अपनी प्रतिष्ठा को थोड़ा पीछे रखकर इस साल के एससीओ विवादों को धुला दे, क्योंकि चीन के साथ संबंध सुधारना मोदी की वर्तमान प्रार्थमिकता है।” ट्रंप के रुख से आहत मोदी जान गए हैं कि भारत के पास कूटनीतिक दांव के विकल्प सीमित हैं। इसलिए मोदी सरकार ने विदेश नीति के अन्य विकल्प तलाशने का निर्णय किया है चीन से हाथ मिलाना इसी का अंग है। बीजिंग भारत की दुविधा को समझता है और उसकी गणना में भारत के अमेरिका के पाले में जाने से अच्छा है स्वतंत्र व तटस्थ भार उसके पास आ जाए। विश्लेषकों को उम्मीद है कि भारत और चीन सीमा से सेना हटाने, व्यापार और वीजा नियमों में ढील, जलवायु सहयोग, और जन-संपर्क को बढ़ाने जैसे कई छोटे कदमों की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि इस सम्मेलन से बड़े नीति निर्णयों की उम्मीद नहीं है, फिर भी विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके प्रतीकात्मक महत्व को कम करके नहीं आँकना चाहिए। ओलेंडर के शब्दों में, यह शिखर सम्मेलन प्रतीकों के बारे में है और बहुत शक्तिशाली प्रतीकों के बारे में। सम्मेलन के बाद मोदी चीन से रवाना हो जाएंगे, जबकि पुतिन बीजिंग में होने वाली द्वितीय विश्व युद्ध की सैन्य परेड में भाग लेने के लिए सप्ताहभर चीन में रहेंगे - जो रूस के बाहर उनका एक असाधारण रूप से लंबा दौर होगा।

हैल्थ इंश्योरेंस और...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर जीएसटी को शुल्क कर दिया जाए। अब यह रिपोर्ट परिषद के पास है, जहाँ अंतिम निर्णय राज्य के वित्त मंत्रियों और केंद्र सरकार के हाथ में होगा। कुछ वैकल्पिक सुझाव भी विचाराधीन हैं - जैसे जीएसटी को आंशिक रूप से घटाकर 5 प्रतिशत या 12 प्रतिशत करना, या वरिष्ठ नागरिकों अथवा 5 लाख तक की पॉलिसियों के लिए राहत देना। ये आधे-अधूरे उपाय सरकार को राजस्व में अधिक नुकसान से तो बचा लेंगे, लेकिन बीमा को वास्तव में सुलभ बनाने के उद्देश्य को कमजोर कर सकते हैं।

राज्यों की अपनी चिंताएँ जायज़ हैं। बीमा प्रीमियम पर जीएसटी से हर साल 2,600 करोड़ से 9,700 करोड़ तक का राजस्व आता है, जो छूट के दायरे पर निर्भर करता है। ऐसे समय में जबकि, कई राज्य वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं, इस राजस्व को छोड़ना आसान नहीं होगा। बीमा कंपनियाँ भी चिंतित हैं। अगर जीएसटी हटा दिया गया, तो उन्हें अपनी सेवाओं पर मिलने वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, जिससे उनके मुनाफे पर असर पड़ सकता है। इन मुद्दों पर परिषद में तीखी बहस की संभावना

है। फिर भी, छूट के पक्ष में दलील बहुत मजबूत है। भारत के पक्ष में समय से बीमा की कम पहुँच और अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा की दोहरी चुनौतियों से जूझ रहा है। इसका मतलब है कि बीमारी के समय या कमाने वाले सदस्य की मृत्यु की स्थिति में परिवार अपनी बचत पर निर्भर रहते हैं। जीएसटी को हटाकर सरकार की तरफ से यह संकेत जाएगा कि वह बीमा के जरिए लोगों को जोखिम बाँटने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। जिससे परिवारों की वित्तीय असुरक्षा कम होगी। यह वित्तीय समावेशन (फायनैशियल इन्क्लूजन) और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यापक नीति के अनुरूप भी है।

इस निर्णय का समय भी बहुत अहम है। जीएसटी परिषद की सितंबर बैठक में टैक्स स्लैब्स को बदलकर उन्हें आसान बनाने की संभावना है। इसमें 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत वाले स्लैब हटाकर सिर्फ दो दरें, 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत रखने का प्रस्ताव है। इस व्यापक सुधार के बीच बीमा पर छूट सबसे ज्यादा उपभोक्ता-हितैषी कदम के रूप में उभर सकती है। सरकार इसे दिवाली तोहफे के रूप में पेश कर सकती है, और इसे अक्टूबर में त्योहारी सीजन

से पहले लागू किया जा सकता है। इससे बीमा कंपनियों को अपने उत्पादों की कीमतें फिर से तय करने और बाज़ार में उन्हें अधिक आकर्षक बनाने का मौका मिलेगा।

अंततः यह मुद्दा इस पर निर्भर करता है कि परिषद वित्तीय विवेक और सामाजिक ज़रूरत के बीच संतुलन कैसे बनाती है। भारत की बचत प्रणाली पहले ही बदल रही है, लोग अब सोना और अचल संपत्ति के बजाय वित्तीय साधनों में निवेश कर रहे हैं।

सुरक्षा (प्रोटेक्शन) की लागत को कम करना इस प्रवृत्ति को और मजबूत करेगा। यह एक ऐसा समाज बनाने में मदद करेगा जो ज्यादा स्वस्थ और आर्थिक रूप से सुरक्षित हो, जहाँ बीमारी या अकाल मृत्यु से लोग कम प्रभावित हों।

अगर परिषद यह साहसिक निर्णय लेती है और पूर्ण छूट देती है, तो यह सुधार जीएसटी के लागू होने के बाद से उपभोक्ता हित में लिए गए सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में गिना जाएगा। यह दिखाएगा कि टैक्स सिस्टम केवल राजस्व जुटाने के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक प्रगति को सक्षम बनाने के लिए भी है।

आप नेता सौरभ भारद्वाज पर ईडी का छापा

नयी दिल्ली, 26 अगस्त। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में 24 अस्पतालों के निर्माण से जुड़े 5,590 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के घर सहित 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ईडी सूत्रों ने कहा कि फिलहाल तेरह स्थानों पर तलाशी चल रही है। धन शोधन निवारण (पीएमएलए) मामला 2018-19 में हुए कथित

दिल्ली अस्पताल निर्माण से जुड़ा हुआ है। उल्लेखनीय है कि निर्माण में देरी होने के कारण अस्पतालों की लागत बढ़ गई। 2018-19 में आप सरकार ने अस्पतालों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की थी, हालांकि परियोजनाएँ समय पर पूरी नहीं हो सकीं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्यवाही प्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है।

राहुल की वोट अधिकार यात्रा में शामिल हुई प्रियंका गांधी

पटना, 26 अगस्त। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा आज बिहार में चल रही मतदाता अधिकार यात्रा में अपने भाई राहुल गांधी के साथ शामिल हुईं। यात्रा के दसवें दिन सुपौल जिले में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। पहली बार प्रियंका गांधी इस अभियान में शामिल हुईं और राहुल गांधी के साथ खुले वाहन में लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान माहौल उत्साहपूर्ण रहा और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में नई स्फूर्ति देखी गई।

अमेरिका ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) किए जाएंगे या गोदाम से निकाले जाएंगे। ट्रंप ने इस महिने की शुरुआत में भारत के सामान पर टैरिफ को 25 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने की घोषणा की थी, जो रूस से तेल खरीदने के कारण लगाया जा रहा है। अमेरिका की यह समयसीमा 27 अगस्त को खत्म हो रही है।

उपराष्ट्रपति के चुनाव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है उन्हें खुद भी कल्पना नहीं थी। तेलुगु नेता की व्यक्तिगत साख पर किसी भी प्रकार की चोट जल्द ही पूरे समुदाय के अपमान का रूप ले सकती है। इतिहास गवाह है कि ऐसी भावनाएँ कभी-कभी राजनीति को हिला कर रख देती हैं।

जैसे-जैसे उपराष्ट्रपति चुनाव की घड़ी नजदीक और इसे तेलुगु अस्मिता पर प्रहार माना जा सकता

है। एक आम चुनाव तेलुगु अस्मिता बनाम गठबंधन अनुशासन का रंग लेने लगा है। यदि तेलुगु देशम एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी रहती है या फिर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराती है-दोनों ही स्थितियाँ आने वाले दिनों में न केवल चुनाव परिणाम, बल्कि आंध्र तथा तेलंगाना की राजनीतिक दिशा भी तय कर सकती हैं। यह सिर्फ एक वोट नहीं, एक भावनात्मक संकेत हो सकता है।

मोदी ने ट्रंप के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तो हाल के हफ्तों में ट्रंप द्वारा चार बार फ़ोन कॉल करने के बावजूद मोदी ने जवाब देने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट में उन सटीक तारीखों का जिक्र नहीं किया गया है जिन पर कथित तौर पर कॉल किए गए थे। इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक, भारतीय अधिकारियों ने इन कॉल्स पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की थी और स्वयं, राजीव दत्ता, जो एक आर.पी.एस. अधिकारी हैं, नियमानुसार किसी भी मूर्ति का अनावरण नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि इस मामले में पिछले वर्ष एफ.आई.आर. भी दर्ज कराई गई परन्तु, राजकीय दबाव के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई। बल्कि एक ही

वर्ष में मामले पर एफ.आर. भी लगा दी गई। अदालत ने याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए तथ्यों और उपलब्ध फोटो को रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा कि इस मामले में राजनैतिक दबाव के चलते याचिकाकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अदालत ने यह भी माना कि वर्तमान

लोकसभा अध्यक्ष के ओ.एस.डी. राजीव दत्ता एक आर.पी.एस. अधिकारी हैं, जो सरकारी नियमानुसार किसी भी मूर्ति का अनावरण नहीं कर सकते और आरोपियों ने इसमें कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है। इसलिए मुख्य सचिव इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई कर मामले का निस्तारण करें।

MARUTI SUZUKI

BALENO के साथ, हर राह आसान।

इस गणेश चतुर्थी, विघ्नहर्ता के आशीर्वाद और बलेनो की शानदार सवारी से हर चुनौती को पार करें।

3 years

100 000 km WARRANTY*
EXTENDABLE UPTO 6 YEARS

REGAL EDITION
GET COMPLIMENTARY PACKAGE OF UP TO
₹ 51 480^

THE NEW AGE
BALENO
TECH GOES BOLD

360 व्यू कैमरा

श्रेणी में पहला

हेड अप डिस्प्ले

हर मॉडल में 6 एयरवैग ~

इन-बिल्ट सुजुकी कनेक्ट

DRIVE HOME THE BALENO AT JUST
₹4 999#
per month.

₹ 1 17 100**
तक के लाभ

कीमत ₹ 6.74 लाख^ से शुरू
मान्य प्रमाणपत्र जमा करने पर अतिरिक्त स्कैपेज बोनस उपलब्ध है

स्केन करें और निकट के शोरूम से जुड़ें

आज ही ई-बुक करें @
WWW.NEXAEXPERIENCE.COM

हमसे यहां संपर्क करें
1800-200-[6392]
1800-102-[6392]

BIKANER: NEXA JAIPUR ROAD (AURIC MOTORS PH: 7230081665), NEXA GANGANAGAR ROAD (VIPUL MOTORS PH: 9257041501) JHUNJHUNU: NEXA JHUNJHUNU CENTRAL (AURIC MOTORS PH: 7412087314), CHIRAWA: NEXA PILANI ROAD (AURIC MOTORS: 8875012681), SUJANGARH: NEXA CHHAPAR ROAD (AURIC MOTORS: 8875011580).

^ विस्तृत नियम और शर्तों के लिए कृपया अपने नजदीकी डीलरशिप पर जाएं. ऑफर सरीदे गए मॉडल और वैरिएंट के आधार पर भिन्न हो सकते हैं. **सभी ऑफर केवल NEXA डीलरों द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते हैं. मारुति सुजुकी बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय ऑफर वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखती है. रचनात्मक प्रस्तुति. *एयरवैग सहित सूखा सुविधाओं के कामकाज के विवरण के लिए, कृपया उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें. *3 साल या 100000 किमी. जो भी पहले हो. *EMI @ ₹4999 माहक अपग्रेड (एग्रेसी कार का एक्वाइजिशन मूल्य 3.40 लाख रुपये) बलेनो सिग्ना वैरिएंट में करने के लिए एक स्क्रीन है. बैलूत फाइनैस EMI की गणना 9.5% ब्याज दर पर की जाती है. बैलूत EMI कुल लोन राशि का 30% और 5 वर्ष की लोन अवधि है. बैलूत फाइनैस स्क्रीन बुनियादी फाइनैसों द्वारा प्रदान की जाती है. फाइनैस के निर्णय पर फाइनैस किया जाता है और ग्राहक की प्रोफाइल के आधार पर भिन्न हो सकता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने निकटतम नेक्सा डीलर या टोल-फ्री नंबर पर संपर्क करें.

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हथ्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय: पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स: 0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स: 0294-2410146, अजमेर कार्यालय:-राष्ट्रदूत भवन, चुंजी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स: 0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रवेम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908